>

Title: Situation arising due to suicides committed by the farmers in the country.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शून्य काल में एक महत्वपूर्ण विषय उठाने की अनुमति दी। वर्ष 2011 में 14 हजार से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। More than 14,000 farmers committed suicide in the year 2011. अभी इस 2012 के वर्ष में जो सूचनाएं आ रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये संख्या शायद और बढ़ जाएगी। खाद के दाम बेहिसाब बढ़ गए हैं, बीजों, पेस्टीसाइड्स, बिजली और सिंचाई के दाम बढ़े हुए हैं। इसलिए किसान के सामने भारी विपत्ति एवं कठिनाई है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस सम्पूर्ण नीति के बारे में गहराई से विचार करने की जरूरत है। इसका एक परिणाम यह हो रहा है कि किसान खेती से अलग होता जा रहा है और बहुत से किसानों ने खेती छोड़ कर दूसरी तरफ आने का प्रयास किया है। इसके अनेक सामाजिक परिणाम होंगे, सोशल कांसीक्वेंसिस बहुत भारी होंगे। ये लोग खेती छोड़ कर शहरों की तरफ आएंगे और शहरी नौकरियों के ऊपर दबाव पड़ेगा। इसलिए इस प्रश्न पर, क्योंकि खाद के दाम जिस हिसाब से बढ़ाए जा रहे हैं, बिजली और सिंचाई के दाम किसान के लिए जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, वे बहुत अन्यायपूर्ण हैं। वे खेती और देश के लिए बहुत घातक हैं और इस बार क्योंकि सूखा पड़ा है, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में किसान के ऊपर पहले से ही विपत्ति है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगा कि इस बारे में किसानों की आत्महत्या को रोकने के बारे में और उनकी खेती लाभकारी बनाई जाए, वह उसे छोड़ कर न जाए, इसके बारे में सरकार की क्या नीति है? खाद का दाम कम करने के बारे में सरकार का क्या विचार है? किसान जगह-जगह पर आंदोलन कर रहा है, इसलिए खाद का दाम घटना चाहिए। जितने भी इन्पुट्स हैं, किसान के लिए जितने भी आवश्यक इन्पुट्स हैं, उन सब के दामों में कमी होनी चाहिए। इस तरह से खेती को लाभकारी बनाया जाना चाहिए। कभी-कभी हम सुनते हैं कि किसानों की सब्सिडी समाप्त की जायेगी, यह और भी खतरनाक होगा। इसलिए एक पूरी विस्तृत, कॉप्रीहेंसिव पॉलिसी की जरूरत है, जिसमें किसान खेती को और अधिक मनोयोग से कर सकें, खेती लाभकारी बनाई जा सके और देश के उत्पादन में उसका योगदान हो।

एक और कठिनाई इस समय कपास के क्षेत्र में, कॉटन के मामले में आ रही है और जो स्थिति है, वह पिछले साल की तुलना में ज्यादा खतरनाक पैदा हो रही है। कॉटन पिछले साल से इस साल कम हो रही है। कॉटन के बारे में, कपास के बारे में सरकार ने जो एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट की नीति रखी है, उससे भी किसान प्रभावित हो रहा है। यह बी.टी. कॉटन और उससे सम्बन्धित जो सरकार की नीति थी, उसका भी किसान को बहुत नुकसान हो रहा है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि बहुत से किसानों की आत्महत्या इस कॉटन के क्षेत्र में हुई है, इसलिए इस कपास की नीति के बारे में भी सरकार को गहराई से विचार करना चाहिए, क्योंकि, वह केवल किसान से ही सम्बन्धित नहीं है, उसका परिणाम टैक्सटाइल पर भी पड़ता है, उसका परिणाम हमारी गारमेंट इंडस्ट्री पर भी पड़ता है तो यह इस समय एक गम्भीर समस्या है।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा और यह जानना चाहूंगा कि इस बारे में सरकार की नीति क्या है और इसको कितना शीघ्र वह सुधार कर किसानों को राहत पहुंचाएगी?

MR. CHAIRMAN :

Shri P.L. Punia,

Shri Ganesh Singh and

Shri Govind Prasad Mishra may be allowed to associate with the matter raised by Dr. Murli Manohar Joshi.